प्रमोद कोहली से पहले जे.
-
सत पाल, -याचिकाकर्ता
बनाम

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और

एक अन्य,-प्रतिवादी
सी.डब्ल्यू.पी.नं. **1988** का **941**
19 नवंबर, **2008**

भारत का संविधान*, **1950—***अनुच्छेद। ***226-***पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियम और आदेश*,* खंड ***I-*** एक नियमित व्यक्ति की समाप्ति ***9*** वर्ष का बेदाग सेवा रिकॉर्ड रखने वाला कर्मचारी ***-*** अस्थायी सेवाएँ—समाप्ति को उचित ठहराने का एकमात्र आधार—इसमें कोई कमी नहीं याचिकाकर्ता की सेवा ***-*** कनिष्ठ व्यक्तियों की सेवा में बनाए रखना याचिकाकर्ता- अत्यंत मनमाने ढंग से सेवा समाप्ति एक न्यायिक प्राधिकारी द्वारा मनमौजी तरीके से-याचिका की अनुमति दी गई सभी परिणामी लाभ.

यह निर्धारित किया गया है। कि कि जिला न्यायाधीश के पद पर एक न्यायिक प्राधिकारी कैसा है किसी कर्मचारी की सेवाएँ मनमाने ढंग से समाप्त कर सकता है। याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति को उचित ठहराने का एकमात्र आधार यह है
याचिकाकर्ता अस्थायी थे। मैंने सर्विस रिकार्ड मंगवाया है याचिकाकर्ता का. हालाँकि मैंने नियुक्ति आदेश पहले ही नोट कर लिया है याचिकाकर्ता का जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं हालाँकि, छह महीने की अवधि के लिए तदर्थ और अस्थायी थे याचिकाकर्ता को 15 सितम्बर 1972 के आदेश द्वारा नियमित कर दिया गया उत्तरदाताओं का तर्क है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं थीं पूर्णतः अस्थायी नहीं हो सकता और न ही इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। कोई और मैदान नहीं समाप्ति के आक्षेपित आदेश में जो कुछ भी उल्लेख किया गया है। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि कनिष्ठ लिपिकों की संख्या बहुत अधिक है याचिकाकर्ता. इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जूनियर नियमित थे कर्मचारी एवं याचिकाकर्ता अस्थायी थे। याचिकाकर्ता की सेवाएं हैं
द्वारा अत्यंत मनमाने एवं मनमौजी ढंग से समाप्त कर दिया गया जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजपुर। उन्होंने इसका पूर्ण अभाव व्यक्त किया है न्यायिक प्राधिकारी होते हुए भी न्यायिक मस्तिष्क।

सतपाल बनाम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और दूसरा (प्रमोद कोहली, जे.)

न्यायिक प्राधिकारी का ऐसा कार्य जिसे अन्यथा सुधारने का कार्य सौंपा गया है दूसरों की गलतियों की सराहना नहीं की जा सकती.

(पैरा 5 एवं 7)

से. म. मुंजाल, याचिकाकर्ता के वकील।
एसएस साहू, एएजी, पंजाब।

परमोद कोहली, जे.
(1) याचिकाकर्ता 19 दिसंबर 1980 के आदेश से व्यथित है जिला एवं सत्र द्वारा स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं न्यायाधीश, फिरोजपुर। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को संक्षेप में बताया गया, जिससे इसकी ओर अग्रसर हुआ वर्तमान याचिका दाखिल करने का तात्पर्य यह है कि याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया था क्लर्क ने आदेश दिनांक 7 जुलाई, 1971 द्वारा वेतनमान रु. 110-250 छह महीने की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर। उनका नियुक्ति आदेश है इस प्रकार देखा गया:- "आपको इस कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना गया है रुपये के लिपिक ग्रेड में. 110-250 प्लस सामान्य भत्ते जैसा कि नियमों के तहत पूरी तरह से अस्थायी आधार पर स्वीकार्य है। आपकी सेवाएँ बिना किसी रोक-टोक के समाप्त की जा सकती हैं सूचना। यदि आपको दी गई नियुक्ति स्वीकार्य है आपको प्राप्त होने के बाद इस कार्यालय में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना चाहिए आपने सी चीफ मेडिकल से चिकित्सकीय जांच करायी अधिकारी, फ़िरोज़पुर 13 जुलाई, 1971 को।
(2) आरोप है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं नियमित कर दी गईं 15 सितंबर, 1972 को उपरोक्त वेतनमान में। उसके बाद याचिकाकर्ता सात वेतनवृद्धियाँ अर्जित कीं और इसे पार करने का दावा किया गया दक्षता बार. आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता इसके बाद, 11 अगस्त, 1973 को स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त हुए और पूर्ण मनोयोग से कार्य किया समर्पण और बेदाग रिकॉर्ड के साथ। याचिकाकर्ता को फिर से पदोन्नत कर दिया गया 1 अप्रैल, 1979 से वेतनमान में वरिष्ठ लिपिक के रूप में रु. 510-800. हालाँकि याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं आदेश दिनांक 19 दिसंबर, 1980 द्वारा। समाप्ति आदेश पढ़ता है
निम्नानुसार:-
"वरिष्ठ उप के लिए श्री सतपाल स्टेनो-टाइपिस्ट की सेवाएँ न्यायाधीश,

फिरोजपुर, जिनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर की गई थी, को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(एसडी.). . दिनांक 19 दिसम्बर, 1980. जिला एवं सत्र
न्यायाधीश,
फिरोजपुर.

(3) अपनी बर्खास्तगी से दुखी होकर, उसने इसके तहत अपील दायर की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों का अध्याय 18-ए खंड I. हालाँकि, याचिकाकर्ता की यह अपील खारिज कर दी गई दिनांक 4 सितम्बर 1981 के आदेश द्वारा इस आधार पर कि अपील उपरोक्त प्रावधान के तहत केवल वहीं निहित है जहां समाप्ति होती है दंड आदि का। अपीलीय प्राधिकारी (माननीय न्यायाधीश) का आदेश इस न्यायालय को इस आधार पर एक रिट याचिका में चुनौती दी गई अपील विचारणीय थी. रिट याचिका भी खारिज कर दी गई सीमा में. याचिकाकर्ता ने माननीय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट। विशेष अनुमति याचिका भी ख़ारिज कर दी गई यह मानते हुए कि अपील सक्षम नहीं थी, हालाँकि, याचिकाकर्ता था संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने की छूट दी गई है आदेश के खिलाफ भारत के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 23 नवंबर, 1987 को पारित आदेश के तहत योग्यता के आधार पर सेवामुक्त किया गया 1982 की सिविल अपील संख्या 1255 में। यह इन परिस्थितियों में है वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उसे चुनौती देते हुए दायर की गई है समाप्ति. बर्खास्तगी के विवादित आदेश को प्राथमिक रूप से चुनौती दी गई है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर यह दावा किया जा रहा है वह जिला न्यायालय का नियमित कर्मचारी था। याचिकाकर्ता ने भी यह कहते हुए शत्रुतापूर्ण भेदभाव का आरोप लगाया कि लगभग 50 व्यक्ति कनिष्ठ हैं
उन्हें सेवा में बरकरार रखा गया और याचिकाकर्ता पर मनमाने ढंग से काम किया गया ख़त्म कर दिया गया.

(4) रजिस्ट्रार की ओर से लिखित बयान दाखिल किया गया है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ-साथ जिला और सत्र न्यायाधीश, फिरोजपुर. आक्षेपित आदेश को केवल आधार पर उचित ठहराने का प्रयास किया गया है
आधार यह है कि याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी शर्तों के अनुरूप है उसकी नियुक्ति, एक अस्थायी कर्मचारी होने के नाते, बिना समाप्त किये जाने योग्य है कोई भी कारण बताना. यह नोट करना प्रासंगिक है कि पहले दायर किए गए उत्तर में इस न्यायालय में और अपील में माननीय अपीलीय न्यायाधीश के समक्ष भी याचिकाकर्ता द्वारा पसंद

किए जाने पर, यह विशेष रूप से स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता एक समर्पित कर्मचारी था और उसका 9 साल की सेवा का बेदाग सेवा रिकॉर्ड था।

सतपाल बनाम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और दूसरा (प्रमोद कोहली,!.)

रिट में दिया गया एक विशिष्ट कथन याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को दिनांकित आदेश द्वारा नियमित किया गया था 15 सितम्बर, 1972 को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। के बारे में याचिकाकर्ता को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति देने की बात कही गई है कर्मचारियों की संख्या का 50%, दोनों स्थायी और अस्थायी, थे शासन के निर्देशों के आधार पर वरिष्ठ लिपिक के रूप में पदनामित किया गया है। वरिष्ठ लिपिक के रूप में याचिकाकर्ता की पदोन्नति/पदनाम भी विवादित नहीं है। याचिकाकर्ता की सेवा में कोई कमी नहीं बताई गई है। जवाब में कनिष्ठों को बनाए रखने की बात भी स्वीकार की गई है।

(5) उपरोक्त परिस्थितियों में मुझे यह देख कर कष्ट हो रहा है कि कैसे जिला न्यायाधीश के स्तर का न्यायिक प्राधिकारी इसे समाप्त कर सकता है किसी कर्मचारी की मनमाने ढंग से सेवाएँ देना। के लिए एकमात्र आधार याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने को उचित ठहराएं अस्थायी थे. मैंने याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड मांगा है। हालाँकि मैंने याचिकाकर्ता का नियुक्ति आदेश पहले ही नोट कर लिया है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि याचिकाकर्ता की सेवाएँ तदर्थ थीं हालाँकि, याचिकाकर्ता छह महीने की अवधि के लिए अस्थायी था 15 सितम्बर 1972 के आदेश द्वारा नियमित किया गया फ़ाइल पर आदेश इस प्रकार है:-

"इस कार्यालय में कार्यरत निम्नलिखित क्लर्कों की सेवाएँ तदर्थ/अस्थायी आधार पर एतद्द्वारा नियमित किया जाता है
रु. के ग्रेड में अस्थायी/स्थानापन्न क्लर्क। 110-4-130-5-180-6-210-8-250। में उनकी वरिष्ठता तय है क्रमानुसार उनके नाम नीचे दिये गये हैं:-

1. श्री जुलदीप सिंह, अहलमक्टेड।

2. श्री राजेश कुमार, अहलटनाद।

3. श्री राजेश कुमार, प्रतिलिपि लिपिक।

4. श्री वेद प्रकाश, अहलमद।

जे श्री जन राज, अहलमद।

6. श्री राजिंदर कुमार, प्रतिलिपिकार।

7. श्री मंगत राय, एल.आर.सी.

8. श्री सत पॉल, एल.आर.सी.

850 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2008(2)

9. श्री कुलदीप कुमार स्टेनो-टाइपिस्ट,
10. कुमारी रमेश कुमारी, एल.आर.सी.

(एसडी.). . दिनांक 15 सितम्बर 1972. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फ़िरोज़पुर।"

(6) उपरोक्त आदेश के अनुसार, 9 व्यक्तियों सहित याचिकाकर्ताओं को रुपये के वेतनमान में नियमित किया गया था। 110-250 और परिणामस्वरूप उनकी वरिष्ठता भी तय की गई। याचिकाकर्ता सीनियर पर खड़ा है। क्रमांक 7 अर्थात उक्त क्रम में उनसे कनिष्ठ दो व्यक्ति थे वरिष्ठता का. नियमितीकरण का आदेश भी विधिवत परिलक्षित होता है सेवा पुस्तिका मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई। यह सामान्य ज्ञान के लिए है जिसकी नियुक्ति पर न्यायिक नोटिस भी लिया जा सकता है सरकारी कर्मचारी, उसे प्रारंभ में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है नियमित आधार, जो मुख्य रूप से परिवीक्षा अवधि है, लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब यह है कि उसकी सेवाएँ बिना किसी कानून के संरक्षण के हैं। बिना किसी खिंचाव के कल्पना की दृष्टि से याची के नियमितीकरण का आदेश हो सकता है इसे पूरी तरह से एक अस्थायी/डब्ल्यूएचओसी व्यवस्था माना जाता है। मेरा विचार है, तथ्यों से यह और भी मजबूत हुआ कि याचिकाकर्ता इसमें लगा रहा नौ वर्ष की अवधि तक सेवा की और न केवल वेतन वृद्धि अर्जित की को भी एक उच्च पद पर रखा गया और वरिष्ठ के रूप में नामित किया गया क्लर्क कौन सा तथ्य उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार और स्वीकृत किया गया है

7) इन परिस्थितियों में, उत्तरदाताओं का तर्क है कि याचिकाकर्ता की सेवाएँ पूर्णतः अस्थायी नहीं थीं और नहीं हो सकतीं स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. किसी भी अन्य आधार का उल्लेख नहीं किया गया है समाप्ति के आक्षेपित आदेश में. यह भी स्वीकृत स्थिति है याचिकाकर्ता से कई कनिष्ठ लिपिक हैं। यह भी नहीं हो सकता कल्पना की गई कि जूनियर नियमित कर्मचारी थे और याचिकाकर्ता थे अस्थायी। मेरा सुविचारित विचार है कि याचिकाकर्ता की सेवाएँ द्वारा अत्यंत मनमाने एवं मनमौजी तरीके से समाप्त कर दिया गया है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजपुर। उन्होंने इसका पूर्ण अभाव व्यक्त किया है न्यायिक प्राधिकारी होते हुए भी न्यायिक मस्तिष्क। की ऐसी हरकत
न्यायिक प्राधिकारी जिसे अन्यथा सुधार का कार्य सौंपा गया है दूसरों की गलतियों की सराहना नहीं की जा सकती.

याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत किया गया। मैं यह तय करने के लिए किसी का जिक्र नहीं कर रहा हूं पूर्वसर्ग, जब तथ्य इतने स्पष्ट हों तो किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं होती और साफ।

(8) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं विवादित आदेश को रद्द करता हूं दिनांक 19 दिसंबर, 1980 को समाप्ति और पुनः बहाल करने का निर्देश याचिकाकर्ता तुरंत. सामान्य परिस्थितियों में, मेरे पास होता कर्तव्यों का पालन न करने पर याचिकाकर्ता को वेतन देने से इनकार कर दिया अंतराल के दौरान. हालाँकि, दी गई परिस्थितियों में, जहाँ जिस कृत्य की शिकायत की गई है, वह इतना मनमाना और स्पष्ट रूप से अवैध है, मैं विवश हूं याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ देने के लिए।

आर.एन.आर.

अवीकरण :
स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमितउपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी, हरियाणा।